www.summerexpress.in

समर एक्सप्रेस

सूर्योदय सुबह 5:20 बजे
सूर्यास्त शाम 7:24 बजे

R.N.I NO. CHMUL/25/A1155

• साल-1 • अंक-305 • पृष्ठ-8 • मूल्य-5 रूपये • शुक्रवार 10, जुलाई 2026 • चंडीगढ़ • पंजाब • हरियाणा • हिमाचल • ग्रुप एडिटर : अर्शदीप सिंह समर • एग्जीक्यूटिव एडिटर : नितिन उपमन्यु

न्यूज ब्रीफ

अब महाराष्ट्र में यूसीसी लागू करने की तैयारी

मुंबई| महाराष्ट्र सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में आगे बढ़ गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में बताया कि नियमों का मसौदा तैयार करने के लिए पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के तीन पूर्व जज, एक संवैधानिक एक्सपर्ट भी शामिल हैं।

गाइडेड पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया

नई दिल्ली| भारत ने स्वदेशी पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण कर रक्षा क्षमता को नई मजबूती दी है। परीक्षण के दौरान रॉकेट ने करीब 60 किलोमीटर दूर निर्धारित लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाया। परीक्षण सभी मानकों पर सफल रहा। इसकी मदद से सेना लंबी दूरी से दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला कर सकेगी।

माता वैष्णो देवी जाने वाली ट्रेनें घंटों लेट

जम्मू| जम्मू-कटरा रेलखंड पर चल रहे निर्माण और रखरखाव कार्यों के कारण माता वैष्णो देवी जाने वाली कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। रेलवे के अनुसार कुछ ट्रेनें 12 घंटे तक की देरी से चल रही हैं, जबकि कई गाड़ियों को वैकल्पिक मार्ग से संचालित किया जा रहा है। इसके चलते यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।

सिटीजन रिपोर्टर

अब आप भी बन सकते हैं समर एक्सप्रेस के सिटीजन रिपोर्टर। अपने इलाके की कोई भी समस्या, आयोजन, जानकारी या खबर हमें भेजें। आपके नाम के साथ प्रकाशित की जाएगी। अपनी खबर इस फोन नंबर 8699221114 या ईमेल infosummerexpress@gmail.com पर भेजें।

BOOK YOUR ADVERTISEMENT

If you want to publish your advertisement on our newspaper

समर एक्सप्रेस

CONTACT:
+91 6283 860 059

खाड़ी क्षेत्र में तनाव चरम पर, कतर, कुवैत और बहरीन स्थित अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन-मिसाइल हमलों का दावा

अमेरिका ने चाबहार, 90 सैन्य ठिकानों पर किए हमले; ईरान का भी पलटवार

एजेंसी | वॉशिंगटन/तेहरान

अमेरिका और ईरान के बीच कुछ समय की शांति के बाद एक बार फिर सैन्य टकराव तेज हो गया है। अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर हवाई अभियान चलाते हुए करीब 90 सैन्य और सामरिक ठिकानों को निशाना बनाया। कार्रवाई का उद्देश्य ईरान की उन क्षमताओं को कमजोर करना था, जिनके जरिए वह होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों को खतरे में डाल सकता है।

अमेरिकी हमलों में दक्षिण-पूर्वी ईरान के चाबहार, बंदर अब्बास, कोनारक और अन्य तटीय क्षेत्रों के सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। चाबहार क्षेत्र में बमबारी के दौरान तीन लोगों की मौत हुई और कई स्थानों पर भारी नुकसान हुआ। कुछ रिपोर्टों में रेलवे पुल और सैन्य ढांचे को भी क्षति पहुंचने का दावा किया गया है, हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में वायु रक्षा प्रणाली, तटीय रडार, मिसाइल और ड्रोन भंडारण केंद्र, नौसैनिक संसाधन तथा सैन्य लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को निशाना बनाया गया। इससे एक दिन पहले भी अमेरिका 80 से अधिक ठिकानों पर कार्रवाई कर चुका था। हमलों के जवाब में ईरान ने कतर, कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले करने का दावा किया। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि इन हमलों में अमेरिकी मिसाइल रक्षा प्रणाली, रडार और अन्य सैन्य उपकरणों को नुकसान पहुंचाया गया।

चाबहार क्षेत्र में बमबारी से तीन लोगों की मौत

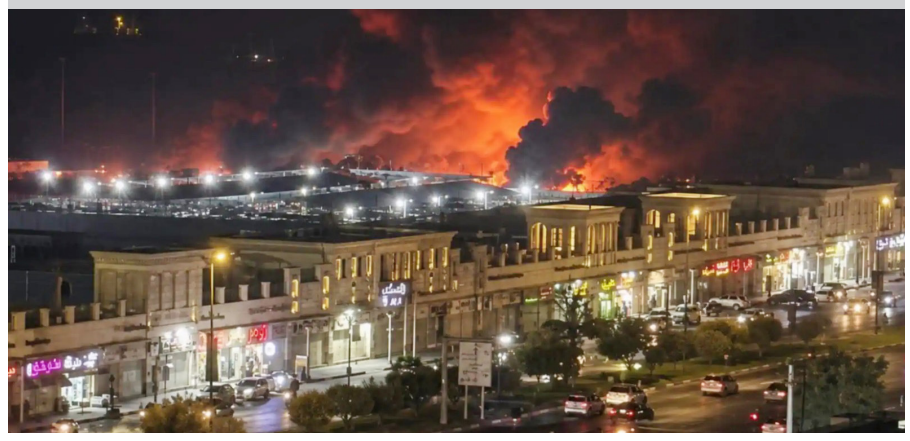

मैं ईरान की 'हिटलिस्ट' में सबसे ऊपरः ट्रम्प

इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों के बाद संघर्षविराम प्रभावी नहीं रहा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ईरान ने हमले जारी रखे तो अमेरिका और कड़ी सैन्य कार्रवाई करेगा। ट्रम्प ने यह भी कहा कि वह ईरान की 'हिटलिस्ट' में सबसे ऊपर हैं, लेकिन अमेरिका किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है।

दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील

संयुक्त राष्ट्र तथा कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह सैन्य टकराव और बढ़ता है तो इसका असर केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री व्यापार और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर भी पड़ सकता है।

खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

संघर्ष तेज होने के साथ पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कतर, बहरीन और कुवैत में कई स्थानों पर हवाई हमले के सायरन बजाए गए, जबकि जहाजरानी कंपनियों ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। इस मार्ग से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और एलएनजी निर्यात होता है।

जसवंत सिंह खालड़ा के हत्यारे पूर्व डीएसपी को तलाशने के आदेश, विवाद हाईकोर्ट पहुंचा

समर न्यूज | चंडीगढ़

मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा हत्याकांड में दोषी करार दिए गए पूर्व पंजाब पुलिस अधिकारी डीएसपी परमजीत सिंह की तलाश के लिए नाभा ओपन जेल प्रशासन ने होशियारपुर पुलिस को औपचारिक निर्देश जारी किए हैं।

जेल प्रशासन ने पुलिस से उन्हें ढूंढकर नियमानुसार हिरासत में लेने और जेल में पेश करने को कहा है। यह कार्रवाई उस समय शुरू हुई, जब निजी मुचलके (पर्सनल बॉन्ड) पर अस्थायी रूप से रिहा किए जाने के बाद वह निर्धारित समय पर जेल वापस नहीं लौटे।

परमजीत सिंह आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं और नाभा ओपन जेल में बंद थे। उन्हें कानूनी प्रावधानों के तहत सीमित अवधि के लिए निजी बॉन्ड पर रिहाई मिली थी। जेल अधिकारियों का कहना है कि रिहाई की अवधि समाप्त होने के बाद भी उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। इसके बाद जेल नियमों के तहत उनकी तलाश की प्रक्रिया शुरू की गई और संबंधित जिला पुलिस को आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया।

इस बीच फिल्म सतलुज का विवाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। मोहाली के व्यक्ति सरवन सिंह ने याचिका लगाकर फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वापस लाने की मांग की है।

परमजीत सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी

जसवंत सिंह खालड़ा 1990 के दशक में पंजाब में कथित फर्जी मुठभेड़ों और अज्ञात शवों के अंतिम संस्कार के मामलों को उजागर करने के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुए थे। वर्ष 1995 में उनका कथित अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। लंबे समय तक चली जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद इस मामले में पंजाब पुलिस के कई अधिकारियों को दोषी ठहराया गया था। इनमें पूर्व डीएसपी परमजीत सिंह भी शामिल हैं, जिन्हें अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

पंजाब पुलिस के दो कर्मचारी नशा तस्करी में गिरफ्तार

तरनतारन में उप निरीक्षक से 300 ग्राम हेरोइन बरामद, फाजिल्का में मुंशी तस्करों के साथ पकड़ा गया

समर न्यूज | चंडीगढ़

पंजाब में नशा तस्करी के मामलों में पुलिस विभाग के ही दो कर्मचारियों की गिरफ्तारी ने विभागीय व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तरनतारन और फाजिल्का से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में एक उप निरीक्षक और एक मुंशी को हेरोइन तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

तरनतारन में तैनात उप निरीक्षक साहिब सिंह को नशा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से करीब 300 ग्राम हेरोइन और नशे की कमाई बरामद

की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अपराध जांच शाखा को सूचना मिली थी कि उप निरीक्षक साहिब सिंह कथित तौर पर अपनी वर्दी का दुरुपयोग करते हुए नशा तस्करी से जुड़ी गतिविधियों में शामिल है।

इस सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक जांच रिपुतापन सिंह की अगुआई में विशेष दल बनाया गया। पुलिस दल ने तरनतारन जिले के गांव मजूपुर निवासी साहिब सिंह से जुड़े झबाल के पास स्थित एक अहाते पर छापेमारी की। इस दौरान 300 ग्राम हेरोइन और कथित नशे की कमाई बरामद की गई। इसके बाद साहिब सिंह को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी गई।

आरोपी पाकिस्तान से आने वाली हेरोइन को पंजाब सहित अन्य राज्यों तक पहुंचाने में मदद करता था। हालांकि पंजाब पुलिस की ओर से इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। दूसरा मामला फाजिल्का जिले के जलालाबाद क्षेत्र से सामने आया है। यहां पुलिस चौकी घुबाया में तैनात मुंशी जोगिंदर सिंह को हेरोइन तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई श्री मुक्तसर साहिब पुलिस ने की।

डीएसपी जलालाबाद गुरसेवक सिंह बराड़ के अनुसार, पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध कार को रोका। तलाशी लेने पर कार में सवार लोगों के कब्जे से 280 ग्राम हेरोइन और एक लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद हुई। जांच के दौरान सामने आया कि कार में तस्करों के साथ पुलिस चौकी घुबाया का मुंशी जोगिंदर सिंह भी मौजूद था। इसके बाद उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।

आरोपियों के घर से नोटों के बंडल मिले, 30 बैंक खाते फ्रीज

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामलाः चंदे की रकम ब्याज पर बांटी, शेयर मार्केट में लगाई

एजेंसी | अयोध्या

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी अनुकल्प मिश्रा को पुलिस गुरुवार सुबह 9 बजे उसके घर लेकर गई। वहां करीब 20 मिनट तक तलाशी ली। घरवालों से भी पूछताछ की।

इससे पहले, बुधवार को पुलिस लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडेय को भी उनके घरों पर लेकर गई थी। इनके भी घरों की तलाशी ली थी। पुलिस ने आरोपियों के रिश्तेदारों के 30 बैंक खाते फ्रीज किए हैं। इनमें आय की तुलना में अधिक लेन-देन मिलने की बात सामने आई है।

वहीं, तीनों के घरों की तलाशी के दौरान पुलिस ने नोटों के बंडल और सोने के जेवर (कान की बालियां, लॉकेट) बरामद किए। साथ ही एक कार भी मिली। हालांकि, पुलिस ने अभी इसका खुलासा नहीं किया कि कितना कैश और सामान किसके घर से बरामद हुआ है? अनुकल्प ने पूछताछ में बताया- मैं और अविनाश शुक्ला चोरी के पैसों को शेयर मार्केट में लगाते थे। लोगों को ब्याज पर देते थे। पैसों को करीबियों और रिश्तेदारों को पैसे देते थे। फिर उनसे अपने खातों में पैसे ट्रांसफर करवाते थे।

वहीं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मंदिर के संचालन और प्रबंधन को अधिक व्यवस्थित एवं पेशेवर बनाने की दिशा में काम कर रहा है।

वेनेजुएला भूकंपः मृतकों की संख्या 3,811 पहुंची

वेनेजुएला| वेनेजुएला में 24 जून को आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,811 हो गई है। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज के अनुसार इस आपदा में 16,740 लोग घायल हुए हैं, जबकि 17,907 लोग बेघर हो चुके हैं। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से वेनेजुएला पर लगे प्रतिबंधों में राहत देने की अपील दोहराई है। वेनेजुएला में संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम डील गगनयान मिशन में भी मिलेगा सहयोग

रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और क्रिटिकल मिनरल्स समेत कई क्षेत्रों में बढ़ा सहयोग

स्वच्छ ऊर्जा और हाई-टेक साझेदारी पर दिया जोर

एजेंसी | मेलबर्न

भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती देते हुए यूरेनियम आपूर्ति समेत रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, व्यापार और क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा की है। मेलबर्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की बैठक के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति भारत के स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम को मजबूती देगी। उन्होंने बताया कि दोनों देश मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर विकसित करेंगे और ऑस्ट्रेलिया के कोकोस (कीलिंग) द्वीप पर स्पेस ट्रैकिंग टर्मिनल स्थापित किया जाएगा, जिससे भारत के गगनयान मिशन को तकनीकी सहायता मिलेगी।

एआई, सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा में भी साथ

दोनों देशों ने ऑस्ट्रेलिया-इंडिया साइबर, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एंड सप्लाई चेन्स पार्टनरशिप शुरू करने पर सहमति जताई है। इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा और डिजिटल तकनीकों में संयुक्त अनुसंधान और सहयोग बढ़ाया जाएगा।

भारत के लिए यूरेनियम क्यों महत्वपूर्ण

भारत परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए यूरेनियम का उपयोग करता है। इससे स्वच्छ बिजली उत्पादन को बढ़ावा मिलता है और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होती है। भारत की परमाणु नीति के तहत आयातित यूरेनियम का उपयोग अंतरराष्ट्रीय निगरानी वाले असैन्य परमाणु रिएक्टरों में किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम आपूर्ति करने वाला पांचवां देश बन गया है। इससे पहले भारत कजाकिस्तान, कनाडा, रूस और उज्बेकिस्तान सहित अन्य देशों से यूरेनियम आयात करता रहा है।

पेज 1 एंकर स्टोरी **प्लॉट का आकार बढ़ाः जीएमएडीए क्षेत्र में नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू; सुविधा प्रमाणपत्र की अवधि चार वर्ष**

संशोधित लैंड पूलिंग पॉलिसी से मोहाली के किसानों को बड़ा फायदा

समर न्यूज | चंडीगढ़/मोहाली

पंजाब सरकार ने ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) क्षेत्र के लिए संशोधित लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू कर दी है। नई नीति के तहत किसानों को पहले की तुलना में अधिक विकसित आवासीय व व्यावसायिक प्लॉट मिलेंगे।

सरकार का कहना है कि संशोधन का उद्देश्य किसानों को विकास प्रक्रिया में अधिक भागीदार बनाना और भूमि अधिग्रहण से जुड़े विवादों को कम करना है। यह संशोधित नीति 6 जुलाई से पूरे जीएमएडीए क्षेत्र में लागू हो गई है। नई व्यवस्था के अनुसार, एक एकड़ या उससे अधिक भूमि देने वाले किसानों को पहले की तरह 1,000 वर्गगज आवासीय प्लॉट का अधिकार रहेगा, लेकिन

व्यावसायिक एससीओ प्लॉट का आकार 200 से बढ़ाकर 210 वर्गगज कर दिया गया है।

वहीं यदि किसान केवल आवासीय प्लॉट का विकल्प चुनते हैं तो उन्हें अब 1,600 के बजाय 1,630 वर्गगज विकसित आवासीय प्लॉट मिलेगा। व्यावसायिक श्रेणी की भूमि देने वाले किसानों के लिए भी प्लॉट का अधिकार 800 से बढ़ाकर 840 वर्गगज प्रति एकड़ कर दिया गया है। सरकार ने किसानों को मिलने वाले सहूलियत प्रमाणपत्र की वैधता भी दो वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष कर दी है। इसके साथ ही किसानों को स्टांप ड्यूटी में दो विकल्प दिए गए हैं। वे या तो विकसित प्लॉट की रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी से छूट प्राप्त कर सकते हैं या फिर पंजाब में कहीं भी जमीन खरीदने पर अधिग्रहित भूमि की कलेक्टर दर के आधार पर छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा प्राथमिकता के आधार पर ट्यूबवेल कनेक्शन की सुविधा की अवधि भी चार वर्ष कर दी गई है।

रियायती दर पर आवासीय प्लॉटः संशोधित नीति का एक महत्वपूर्ण बदलाव यह भी है कि अब औस्टी कोटा के तहत रियायती दर पर आवासीय प्लॉट का लाभ उन किसानों को भी मिलेगा जिन्होंने भूमि के बदले नकद मुआवजा लिया है।

पहले यह सुविधा केवल लैंड पूलिंग विकल्प चुनने वाले किसानों तक सीमित थी। नई व्यवस्था के तहत एक एकड़ भूमि अधिग्रहण पर 200 वर्गगज, एक से 2.5 एकड़ तक 300 वर्गगज और 2.5 एकड़ से अधिक भूमि देने वालों को 500 वर्गगज तक का आवासीय प्लॉट योजना दर पर दिया जाएगा।

स्पेशल लेटर ऑफ इंटेंट

इसके अलावा, आंशिक भूमि स्वामित्व वाले किसानों के लिए स्पेशल लेटर ऑफ इंटेंट की व्यवस्था की गई है। ऐसे किसान अपनी हिस्सेदारी के अनुपात में अधिकार प्राप्त करेंगे और इन विशेष एलओआई का हस्तांतरण भी किया जा सकेगा। पर्याप्त एलओआई जमा होने पर उन्हें पूर्ण प्लॉट आवंटन का अधिकार मिलेगा। सरकार ने यह व्यवस्था ईको सिटी-3 और अन्य टाउनशिप परियोजनाओं पर भी लागू की है।

एसकेएम ने की विरोध की घोषणा

हालांकि, इस संशोधित नीति को लेकर किसान संगठनों की राय एक जैसी नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने सरकार की नई लैंड पूलिंग नीति का विरोध जारी रखने की घोषणा की है। संगठन का कहना है कि यदि किसानों की सहमति के बिना भूमि लेने का प्रयास किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। दूसरी ओर, सरकार का दावा है कि संशोधित नीति किसानों को पहले से अधिक लाभ देने और विकास परियोजनाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है।

चंडीगढ़ में एक क्लिक पर मिलेगा प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड

संपत्ति का स्वामित्व ऑनलाइन होगा सत्यापित, नागरिक 30 दिन के भीतर दर्ज करा सकेंगे आपत्तियां

समर न्यूज | चंडीगढ़

चंडीगढ़ प्रशासन ने संपत्ति रिकॉर्ड को अधिक पारदर्शी और विवाद-मुक्त बनाने की दिशा में नई पहल शुरू की है। इसके तहत शहर की प्रॉपर्टियों का रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे नागरिक एक क्लिक पर किसी भी संपत्ति का स्वामित्व और संबंधित विवरण देख सकेंगे।

इस व्यवस्था का उद्देश्य फर्जी स्वामित्व दावों और धोखाधड़ी पर रोक लगाना है। प्रशासन के अनुसार, प्रारंभिक रिकॉर्ड सार्वजनिक पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति को दर्ज जानकारी पर आपत्ति है, तो वह 30 दिनों के भीतर संबंधित

विभाग के समक्ष अपना दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। तय समय के बाद प्राप्त आपत्तियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों का कहना है कि नई व्यवस्था से संपत्ति खरीद-फरोख्त में पारदर्शिता बढ़ेगी, असली मालिक की पहचान आसानी से हो सकेगी और रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण से विवादों के निपटारे में भी तेजी आएगी। इससे नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत भी कम होगी।